

रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/92.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 23 सितम्बर, 1992/1 आश्विन, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 23 सितम्बर, 1992

संख्या एल० एल० आर० डी(6)-16/91-लेजिसलेशन.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा तारीख 6 सितम्बर, 1992 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश कुटलैहड़ बन सम्पदा (प्रबन्ध का अर्जन) विधेयक, 1992 (1992 का विधेयक संख्यांक 10) को वर्ष 1992

के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित, हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

अंग्रेजी

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव (बिबि) ।

1992 का अधिनियम संख्यांक 19.

हिमाचल प्रदेश कुटलैहड़ वन सम्पदा (प्रबन्ध का अर्जन) अधिनियम, 1992

(राष्ट्रपति महोदय द्वारा तारीख 6 सितम्बर, 1992 को अनुमोदित)

कुटलैहड़ वन के प्रबन्ध के अर्जन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा इससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

उद्देशिका.—पूर्व कुटलैहड़ रियासत के भूतपूर्व चीफ या शासक को कुटलैहड़ वन सम्पदा का प्रबन्ध करने और उससे प्राप्त आय के प्रभाग को प्रबन्धकीय प्रभारों के रूप में विनियोजित करना अनुज्ञात किया गया है ;

और यदि ऐसा प्रबन्ध जारी रखा जाता है, तो सरकार को भारी हानि होगी और व्यक्तियों को अत्यधिक अनजित लाभ होगा ;

और भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में अधिकविध तथ्यों को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, लोक हित में यह आवश्यक है कि कुछ व्यक्तियों को हो रहे ऐसे अनुचित लाभ को जनसाधारण की सामान्य प्रसुद्धि के लिए उपयोग किया जाए।

भारत गणराज्य के तैत्तलीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कुटलैहड़ वन सम्पदा (प्रबन्ध का अर्जन) अधिनियम, 1992 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

- (क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ;
- (ख) "अनुदान" से सरकार द्वारा अनुज्ञात कुटलैहड़ वन का प्रबन्ध अभिप्रेत है ;
- (ग) "प्राप्तिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में अनुदान किया गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी और समनुदेशित हैं ;
- (घ) "कुटलैहड़ वन" से वे वन और बंजर भूमि अभिप्रेत हैं जो, नियत दिन को कुटलैहड़ वन अधीक्षक के प्रबन्ध और नियंत्रण के अधीन हैं और इस अधिनियम की अनुसूची में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित हैं ;

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए कुटलैहड़ वन अधीक्षक से कुटलैहड़ वन अधीक्षक के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त कुटलैहड़ रियासत की संपदा का भूतपूर्व चीफ या शासक अभिप्रेत है ;

(3) "विक्रय" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

अनुदान जिस को अधिनियम लागू होता है।

3. यह अधिनियम, सरकार द्वारा या उसकी ओर से कुटलैहड़ रियासत की सम्पदा के भूतपूर्व चीफ या भूतपूर्व शासक के पक्ष में दिए गए या अनुदत्त वन और बंजर भूमि के प्रबन्ध के सभी अनुदानों, पर्यवेक्षण या नियंत्रण को लागू होगा जिसमें निम्नलिखित सभी या कोई निबन्धन या शर्त अन्तर्निष्ठ हैं, अर्थात् :—

- (क) प्राप्तिकर्ता वनों का प्रबन्ध कर सकेगा और उससे प्राप्त आय के भाग को प्रबन्धकीय प्रभारों के रूप में विनियोजित कर सकेगा ;
- (ख) प्राप्तिकर्ता खड़े वृक्षों या उससे प्राप्त अन्य वन उपज को, भूमि से प्राप्त, यथा-स्थिति, इमारती लकड़ी या वन उपज के बारे में, ऐसे अनुदान का साक्ष्य देने वाले विलेख या राजस्व अथवा वन बन्दोबस्त अभिलेख में विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व (रायल्टी) के संदाय के अधीन रहते हुए, स्वयं अपने उपयोग के लिए, विनियोजित कर सकेगा ;
- (ग) जब भूमि को साफ किया जाता है तो अभिहित दर पर पेड़ का मूल्य संदत्त करना होगा ; और
- (घ) प्राप्तिकर्ता अनुदान के लिए कोई निर्धारण या लगान संदत्त करने का दायी नहीं है या वह केवल अभिहित निर्धारण या लगान संदत्त करने का दायी है।

प्राप्तिकर्ता के अधिकारों का सरकार में निहित होना और अनुदान में अधिकारों का निर्वापन।

4. नियत दिन से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा में अथवा किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, —

- (i) अनुदान निर्वापित हो जाएगा और ऐसी भूमि से बद्ध कोई सेवा या बाध्यता समाप्त हो जाएगी और प्राप्तिकर्ता का ऐसे अनुदान से बद्ध किसी सेवा को करने की किसी शर्त या बाध्यता का पालन करने का दायित्व नहीं होगा ;
- (ii) प्राप्तिकर्ता के वनों या बंजर भूमियों में उस द्वारा धारित सभी अधिकार, हक और हित सभी विल्लंगमों से रहित सरकार में निहित हो जाएंगे।

सरकार द्वारा संदत्त की जान वाली रकम।

5. (1) धारा 4 के अधीन किसी व्यक्ति के अधिकार, हक और हित को सरकार में निहित करने के प्रतिफल में सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्ति को, प्रबन्ध में उस द्वारा उपगत सभी विधिपूर्ण व्ययों को काटने के पश्चात्, वितीय वर्ष 1988-89 के दौरान उसको प्रोद्भूत हुई शुद्ध आय के पांचवे भाग के बराबर रकम, संदत्त करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन संदेय रकम, नियत दिन से पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष, प्रथम जून को संदत्त की जाएगी और ऐसी रकम के संदेय होने की तारीख से संदाय की तारीख तक उस पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से व्याज होगा।

शुद्ध रकम के संदाय की विधि।

6. (1) सरकार, लिखित आदेश द्वारा, लेखा से सम्बन्धित पर्याप्त ज्ञान और अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति को, सरकार द्वारा प्राप्तिकर्ता की धारा 7 में उल्लिखित कटौतियाँ करने के पश्चात्, इस अधिनियम के अधीन संदेय शुद्ध रकम निर्धारित करने के लिए विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) विशेष अधिकारी, संदेय शुद्ध रकम निर्धारित करने के लिए, सरकार के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द की सहायता ले सकेगा, जैसे वह उचित समझे।

(3) जहाँ प्राप्तिकर्ता को संदेय सकल रकम धारा 7 के अधीन काटी जाने वाली कुल रकम के बराबर है या उससे कम है, वहाँ सरकार द्वारा, ऐसे व्यक्ति को कोई संदाय नहीं किया जाएगा।

(4) यदि रकम के निर्धारण के बारे में कोई मतभेद या विवाद हो तो इसे धारा 13 के अधीन मध्यस्थ द्वारा अवधारित किया जाएगा।

7. सरकार, इस अधिनियम के अधीन प्राप्तिकर्ता को संदेय सकल रकम में से निम्न-लिखित राशि काटने के लिए हकदार होगी, अर्थात् :—

- (क) पहले अग्रिम में संदत्त रकम, यदि कोई हो;
- (ख) रकम, यदि कोई हो, जिसे धारा 12 के अधीन सरकार काटने के लिए हकदार है ;
- (ग) नियत दिन से पूर्व सरकार को ऐसे व्यक्ति द्वारा ब्याज सहित देय रकम, यदि कोई हो ;
- (घ) धारा 11 की उप-धारा (2) में यथार्थानित ऋण, बन्धक या वाध्यताओं से सम्बन्धित रकम, यदि कोई हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व, प्राप्तिकर्ता को ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी कटौती के विरुद्ध कारण दर्शित करने का नोटिस दिया जाएगा।

8. (1) प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी जो 16 मार्च, 1992 को या उससे पूर्व कुटलैहड़ विद्यमान कर्म-वन सम्पदा से सम्बन्धित प्रबन्ध में नियुक्त या नियोजित था, और नियत दिन को उक्त चारियों की प्रबन्ध के सम्बन्ध में, ऐसे नियुक्त या नियोजित बना रहा है, जिसका प्रबन्ध का अधिकार सेवाओं का इस अधिनियम के अधीन अर्जित किया गया है, नियत तारीख को, सरकारी कर्मचारी बन जाएगा और अपना पद उसी अवधि के लिए, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबन्धन और शर्तों पर और पेन्शन, उपदान और अन्य मामलों के उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारित करेगा जो उसको अनुज्ञेय होते यदि कुटलैहड़ वन का प्रबन्ध सरकार को अन्तरित और उसमें निहित नहीं होता और ऐसा करना जारी रखेगा जब तक कि सरकार के अधीन उस की सेवा सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दी जाती है या जब तक उसका पारिश्रमिक या सेवा के निबन्धन और शर्तों सम्यक् रूप से सरकार द्वारा परिवर्तित नहीं की जाती हैं :

परन्तु इस उप-धारा में निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में नियत दिन से ठीक पूर्व लागू सेवा शर्तों में उसके अहितकर रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति नियत तारीख से ठीक पूर्व कुटलैहड़ वन के प्रबन्ध में या उसके सम्बन्ध में पूर्णकालिक कर्मचारी था, तो इस प्रश्न को नियत तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सरकार के ऐसे अधिकारी को, जो मण्डल आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, निर्दिष्ट किया जाएगा और वह अधिकारी, इस मामले से सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, इसको ऐसी रीति में विनिश्चित करेगा जैसी वह ठीक समझे और ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कुटलैहड़ वन प्रबन्ध में या उसके संबंध में नियोजित किसी

कर्मचारी की सेवाओं का सरकार को स्थानान्तरण ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या तत्सम प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिपूरक का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

प्रवेश की शक्ति।

9. सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई सरकारी कर्मचारी या धारा 6 के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी, प्राप्तिकर्ता या ऐसे वन और बंजर भूमि के कब्जाधारी किसी व्यक्ति को युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात्, किसी भी समय, उसके कब्जे में किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राथमिक या आनुषंगिक सर्वेक्षण, परीक्षण या अन्वेषण कर सकेगा।

सम्पत्ति का कब्जा परि-
दत्त करने का
कर्तव्य।

10. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कुटलैहड़ वन प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति सरकार को अन्तरित या निहित की गई है, वहां,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसी कोई सम्पत्ति हो, सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर इसे, यथा-स्थिति, सरकार को या ऐसे अधिकारी को तत्काल परिदत्त करेगा;

(ख) कोई व्यक्ति ऐसे निहित किए जाने से तुरन्त पूर्व जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कुटलैहड़ वन के प्रबन्ध या अनुदान से सम्बन्धित कोई बहियां, दस्तावेज या अन्य कागज-पत्र हों, सरकार को उक्त बहियों, दस्तावेजों और कागज-पत्रों का लेखा देने के लिए दायी होगा और इन्हें सरकार या ऐसे व्यक्ति को जिसे सरकार इस निमित्त प्राधिकृत करे, परिदत्त करेगा।

(2) इस धारा में अन्तर्निष्ठ अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार के लिए, इस अधिनियम के अधीन इसे अन्तरित और इसमें निहित सभी सम्पत्तियों का कब्जा लेने के लिए सभी आवश्यक पग उठाना विधिपूर्ण होगा।

निहित किए
जाने के
साधारण
प्रभाव।

11. (1) धारा 4 के अधीन सरकार में निहित सम्पत्ति के अन्तर्गत नीचे विनिर्दिष्ट सम्पत्तियां अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भी समझी जाएंगी, अर्थात्:—

(i) कुटलैहड़ वन के प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्राप्तिकर्ता की सभी स्थिर आस्तियां और उससे सम्बद्ध सभी दस्तावेज;

(ii) नियत दिन से पूर्व की गई किसी सद्भाविक संविदा के अधीन, जो धन उधार लेने या उधार देने अथवा कर्मचारी वृन्द के नियोजन से सम्बन्धित संविदा न हो, अनुदान या प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्राप्तिकर्ता के सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट प्राप्तिकर्ता या कुटलैहड़ वन के प्रबन्ध से बद्ध सभी आस्तियां किसी ऋण, बन्धक या समरूप बाध्यताओं से मुक्त सरकार में निहित होंगी:

परन्तु ऐसे ऋण, बन्धक या बाध्यताएं इस अधिनियम के अधीन प्राप्तिकर्ता को संदेय रकम से सम्बद्ध होंगी।

(3) सरकार या इस द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए किसी बाधा, यदि कोई हो, जो पेश की जा सकती हो, हटाने के पश्चात्, पूर्ण प्रबन्ध या सम्पत्ति अथवा, यथास्थिति, स्थिर आस्तियों और एस प्रबन्ध या सम्पत्ति से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों, जो सरकार द्वारा इसके प्रबन्ध के लिए अपेक्षित हों, का कब्जा लेना विधिपूर्ण होगा।

12. जहाँ सरकार की यह राय हो कि प्राप्तकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति ने, नियत दिन को उसके पश्चात् किसी स्थिर आस्ति का विक्रय, विनिमय, दान, पट्टे या अन्यथा द्वारा व्ययन किया है, या ऐसे व्यक्ति को असम्यक् रूप से फायदा पहुंचाने की दृष्टि से, घटनाओं के सामान्य क्रम से अन्यथा कोई व्यय, दायित्व या बाध्यता उत्पन्न की है और तद्वारा, संपत्ति के उत्तरवर्ती स्वामियों के रूप में सरकार को हानि पहुंचाई है, वहाँ सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राप्तकर्ता को संदेय रकम में से, ऐसी रकम जिसकी उसके विचार में उस द्वारा हानि उठाई गई है, की कटौती करने की हकदार होगी :

परन्तु ऐसी कटौती करने से पूर्व, प्राप्तकर्ता को ऐसी कटौतियों के विरुद्ध, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कारण दर्शित करने का नोटिस दिया जाएगा ।

13. (1) जहाँ नीचे विनिर्दिष्ट मामलों में से किन्हीं के बारे में कोई विवाद पैदा हो जाता है, वहाँ इसका अवधारण सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा जो जिला या उच्च न्यायालय का आसीन या सेवा निवृत्त न्यायाधीश होगा,—

- (क) क्या विशेषाधिकारी द्वारा अवधारित और कुटलैहड़ वन में अधिकारों के निर्वापन के प्रतिफल स्वरूप संदेय रकम इस अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अनुरूप है ;
- (ख) क्या प्राप्तकर्ता से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति या सम्बद्ध कोई अधिकार, दायित्व या बाध्यता सरकार में निहित है ;
- (ग) क्या धारा 12 में निर्दिष्ट कोई करार या अन्य संविदा सद्भावपूर्वक की गई है या नहीं ।

(2) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सभी माध्यस्थमों को लागू होंगे ।

14. कोई व्यक्ति जो,—

- (क) किसी सम्पत्ति को जो अनुदान का भाग है, अपन कब्जा, अभिरक्षा या नियन्त्रण में रखते हुए, दौषपूर्वक सरकार से रोक लेता है ; या
- (ख) सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति को, अनुदान से सम्बन्धित किन्हीं बहियों, दस्तावेजों, कागज-पत्रों को जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में हों, जानबूझकर रोकता है, या देने में असफल रहता है ; या
- (ग) उसके कब्जा, अभिरक्षा या नियन्त्रण में अनुदान से सम्बन्धित कोई आस्ति, लेखा-बहियों, रजिस्ट्रों या अन्य दस्तावेजों को सरकार को परिदत्त करने में असफल रहता है ; या
- (घ) अनुदान का भाग होने वाली किसी सम्पत्ति का सदोषपूर्वक कब्जा अभिप्राप्त करता है या बनाए रखता है ; या
- (ङ) अनुदान का भाग होने वाली किसी सम्पत्ति को सदोषपूर्वक हटाता है या मण्ट करता है ; या
- (च) अनुदान का भाग होने वाली किसी सम्पत्ति का सदोषपूर्वक प्रयोग करता है ;

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अपराधों का
संज्ञान।

15. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान, सरकार या सरकार द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित रूप में किए गए परिवाद के सिवाय, नहीं करेगा।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी, इस निमित्त सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त, प्रथम श्रेणी के किसी मैजिस्ट्रेट के लिए धारा 14 के अधीन दण्ड अधिनिर्णीत करते समय पांच हजार रुपये से अधिक का दण्डादेश अधिरोपित करना विधिपूर्ण होगा।

सद्भावपूर्वक
की गई कार्र-
वाई के लिए
संरक्षण।

16. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी अथवा धारा 6 के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही न होगी।

नियम बनाने
की शक्ति।

17. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए बनाए जाएंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

[धारा 2 (घ) देखें]

कुटलैहड़ वनों के अन्तर्गत वनों का विवरण

	क्रम सं०	ज़िला का नाम	वन का नाम
	1	2	3
सीमांकित संरक्षित वन ।	1.	हमीरपुर	ठेठू
	2.		छलाह
	3.		वन मसलाना
	4.		सेली-सतरुखा
	5.		सामल
	6.	ऊना	पन्याला
	7.		थपल
	8.		बोरु
	9.		रामगढ़-वारला
	10.		रामगढ़-पारला
	11.		टांडा
	12.		कनुड़ा
	13.		सोला सिंगी और भियाम्बी
	14.		चराड़ा
	15.		वन धनेत
	16.		करयारा
	17.		चड़रोली
	18.		सरकारु और घाड़ पलानी
	19.		ओयल-दा-वन
	20.		बेला
	21.		धियूसर
	22.		अकोई-दी-धार
	23.		चंगरेड़ी
	24.		थाना दुलैहड़ी
	25.		टांहा बगवाई
	26.		टीरा अगलौर
	27.		वूसल
	28.		घुगन ककराना
	29.		क्वाड़ी

	1	2	3
	30.	ऊना	मौ
	31.		कटोह
	32.		अमरोह
	33.		अटीया
	34.		चौकी मन्यार
	35.		जोल
	36.		खैरियां
	37.		चौली
	38.		चपलाह गारलां
	39.		सोहारी बडूह
	40.		सरी
	41.		चपलाह- कुटलैहड़ियां
	42.		भरमौत
	43.		छतैहड़
	44.		भियाम्बी
	45.		सुकड़ीयाल
	46.		मतोह
	47.		कोट
	48.		चमीयाड़ी
	49.		बसातर
असीमांकित संरक्षित	1.	ऊना	मछाली
वन	2.		धार चमुखा
	3.		कोटला
	4.		अरल
	5.		सोला सिंगी
	6.		मोमन्यार
	7.		चौकी मन्यार
	8.		बेह
	9.		खरयालत
	10.		धनेत
	11.		हेरु
	12.		द्वियूगली
	13.		थड़ा
	14.		टीहरा
	15.	हमीरपुर	ग्यारह-ग्रां
	16.		पंज-ग्रां ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 19 of 1992.

THE HIMACHAL PRADESH KUTLEHAR FOREST (ACQUISITION OF MANAGEMENT) ACT, 1992

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 6TH SEPTEMBER, 1992)

AN

ACT

to provide for the acquisition of management, supervision and control of the Kutlehar Forest and ancillary matters thereto.

Preamble:—WHEREAS, the Ex-chief or the ruler of the erstwhile princely estate of Kutlehar has been allowed to manage the Kutlehar Forest and to appropriate portion of the income derived therefrom as managerial charges;

AND WHEREAS, such management, if allowed to continue, will result in heavy loss to the Government and huge un-earned profits to the individuals ;

AND WHEREAS, for the purpose of securing the principles laid down in clauses (b) and (c) of Article 39 of the Constitution of India, it is necessary in the public interest that such undue profits to a few persons are utilised for the common benefit of the general public.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Kutlehar Forest (Acquisition of Management) Act, 1992.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) “appointed day” means the date on which this Act comes into force ;

(b) “grant” means the management of Kutlehar Forest permitted by the Government ;

(c) “grantee” means the person in whose favour a grant has been made and includes his heirs, successors and assignees ;

(d) “Kutlehar Forest” means the forests and waste lands which, on the appointed day are under the management and control of the Superintendent, Kutlehar Forest and are more specifically described in the Schedule to this Act.

Explanation.—For the purposes of this clause the Superintendent, Kutlehar Forest means the Ex-chief or ruler of a princely estate of Kutlehar appointed by the Government as the Superintendent, Kutlehar Forest and includes his heirs, successors and assignees ;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

Grant to which Act applies.

3. This Act shall apply to all grants of management, supervision or control over forest and waste lands made or granted by or on behalf of the Government in favour of the Ex-chief or Ex-ruler of a princely estate of Katilehar which contain all or any of the following terms and conditions, namely:—

- (a) the grantee may manage the forests and appropriate part of the income derived therefrom as managerial charges ;
- (b) the grantee may appropriate for his own use trees standing, or other forest produce derived therefrom subject to the payment of royalty at the rates, specified in the deed or revenue or forest settlement records evidencing such grant, in respect of the timber or forest produce, as the case may be, taken out of the land ;
- (c) tree value at a nominal rate has to be paid when the land is cleared ; and
- (d) the grantee is not liable to pay any assessment or rent or he is liable to pay only nominal assessment or rent for the grant.

Vesting of the rights of grantee in Government and extinction of rights in grant.

4. Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or in any contract or in any judgement, decree or order of any court, with effect from the appointed day,—

- (i) the grant shall stand extinguished and any service or obligation attached to such land shall stand abolished ; and the grantee shall have no liability to perform any condition or obligation to render any service/attached to such grant ;
- (ii) all rights, title and interest of the grantee in the forests or waste lands held by him, shall vest in the Government free from all encumbrances.

Amount to be paid by the Government.

5. (1) In consideration of the vesting in the Government the right, title and interest of any person under section 4 the Government shall, subject to the provisions of this Act, pay to such person an amount equivalent of one fifth of the net income, after deduction of all lawful expenses incurred by him in the management, accrued to him during the financial year 1988-89.

(2) The amount payable under sub-section (1) shall be paid on the 1st day of June, every year for a period of five years from the appointed day and shall bear interest at the rate of 9 per cent per annum from the date such amount becomes payable till the date of payment.

Manner of payment of net amount.

6. (1) The Government shall appoint, by order in writing, a person having adequate knowledge and experience in matters relating to accounts, as Special Officer to assess the net amount payable under this Act by the Government to the grantee, after making deductions mentioned in section 7.

(2) The Special Officer may call for the assistance of such Officers and staff of the Government as he may deem fit in assessing the net amount payable.

(3) Where the gross amount payable to the grantee is equal to or less than the total amount to be deducted under section 7 no payment shall be made to such person by the Government.

(4) If there is any difference or dispute regarding assessment of the amount the same shall be determined by the arbitrator under section 13.

7. The Government shall be entitled to deduct the following sums from the gross amount payable under this Act to the grantee, namely:—

Deductions
from gross
amount.

- (a) the amount, if any, already paid in advance ;
- (b) the amount, if any, which the Government are entitled to deduct under section 12 ;
- (c) the amount due, if any, including interest thereon, from such person, to the Government before the appointed day;
- (d) the amount, if any, relating to debts; mortgages or obligations as mentioned in sub-section (2) of section 11 ;

Provided that before making any deduction under this section, the grantee, shall be given a notice to show cause against such deductions, within a period of thirty days from the date of receipt of such notice.

8. (1) Every whole time employee who was on or before the 16th day of March, 1992, appointed or employed in connection with the management of the Kutlehar Forest Estate and has been continued to be so appointed or employed on the appointed day in connection with the said management, the right of management of which has been acquired under this Act, shall, on the appointed day, become an employee of the Government and shall hold his office by the same tenure, at the same remuneration and upon same terms and conditions and with the same rights and privileges as to pension, gratuity and other matters as would have been admissible to him if the management of the Kutlehar Forest has not been transferred to and vested in the Government and shall continue to do so unless and until his employment under the Government is duly terminated or until his remuneration or terms and conditions of service are duly altered by the Government :

Transfer of
services of
existing
employees.

Provided that the conditions of service applicable immediately before the appointed day to the case of any person referred to in this sub-section shall not be varied to his disadvantage.

(2) If any question arises as to whether any person was a whole time employee in or in connection with the management of the Kutlehar Forest immediately before the appointed day, the question shall be referred, within a period of one year from the appointed day, to an officer of the Government, who shall not be lower in rank of the Divisional Commissioner and that officer shall, after giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned in the matter, decide it in such manner as he thinks fit and such decision shall be final.

1947. (3) Notwithstanding anything contained in the Industrial Disputes Act, 1947 or, in any other law for the time being in force, the transfer of

the services of employee employed in or in connection with the management of the Kutlehar Forest to the Government shall not entitle such employee to any compensation under that Act or any other law for the time being in force and no such claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority.

Power of entry.

9. An employee of the Government, authorised in this behalf by general or special order by the Government, or the Special Officer appointed under section 6 may, at any time, after giving the grantee or any other person in possession of such forests and waste lands a reasonable notice, enter upon any land or premises in his possession and make any survey, examination or investigation, preliminary or incidental to the purposes of this Act.

Duty to deliver possession of properties.

10. (1) Where any property in relation to management of Kutlehar Forest has been transferred to and vested in the Government under this Act,—

- (a) every person in whose possession, custody or control any such property may be, shall, on demand by the Government or an officer authorised in this behalf, deliver to the Government or to such officer, as the case may be, forthwith ;
- (b) any person who, immediately before such vesting, has, in his possession, custody or control, any books, documents or other papers, relating to the management of the Kutlehar Forest or grant shall be liable to account for the said books, documents and papers to the Government and shall deliver them up to the Government or to such person as the Government may authorise in this behalf.

(2) Without prejudice to other provisions contained in this section it shall be lawful for the Government to take all necessary steps for taking possession of all properties, which have been transferred to and vested in it under this Act.

General effect of vesting.

11. (1) The property vested in the Government under section 4 shall be deemed to include the properties rights, liabilities and obligations specified below, namely:—

- (i) all the fixed assets of the grantee in relation to the management of the Kutlehar Forest and all documents relating thereto ;
- (ii) all rights, liabilities and obligations of the grantee in relation to the grant or management under any contract entered into bonafide before the appointed day, not being contract relating to the borrowing or lending money, or to the employment of staff.

(2) All the assets specified in clause (i) of sub-section (1) shall vest in the Government free from any debts, mortgages or similar obligations of the grantee or attaching to the management of the Kutlehar Forest:

Provided that such debts, mortgages or obligations shall attach to the amount payable under this Act to the grantee.

(3) It shall be lawful for the Government or any officer authorised by it, to take possession of the entire management or property or, as the case may be, the fixed assets and of all documents relating to such management, or property, which the Government may require for its management, after removing any obstruction, if any, that may be offered.

12. Where the Government is of opinion that the grantee or any other person has on or after the appointed day disposed of any fixed asset, whether by way of sale, exchange, gift, lease or otherwise, or incurred any expenditure, liability or obligation otherwise than in the normal course of events, with a view to benefit unduly such person and thereby caused loss to the Government as succeeding owners of the property, the Government shall be entitled to deduct from the amount payable to the grantee under this Act, an amount which they consider to be the loss sustained by them:

Effect of transactions not bona-fide.

Provided that before making such deduction, the grantee shall be given a notice to show cause against such deductions, within a period of thirty days from the date of receipt of such notice.

13. (1) Where any dispute arises in respect of any of the matters specified below, it shall be determined by an arbitrator appointed by the Government, who shall be a sitting or retired District or High Court Judge,—

Arbitration.

(a) whether the amount determined by the Special Officer and payable in consideration of extinguishment of rights in the Kutlehar Forest is in conformity with the provisions of section 6 of Act;

(b) whether property belonging, or any right, liability or obligation attaching, to the grantee vests in the Government ;

(c) whether any agreement or other contract referred to in section 12 has been entered into bona-fide or not.

(2) Subject to the provisions of this section, the provisions of the Arbitration Act, 1940 shall apply to all arbitrations under this Act.

10 of 1940

14. Any person who,—

Penalties.

(a) having in his possession, custody or control any property forming part of the grant wrongfully withholds such property from the Government; or

(b) willfully withholds or fails to furnish to the Government, or any person authorised in this behalf by the Government, any books, documents, papers relating to the grant which may be in his possession, custody or control ; or

(c) fails to deliver to the Government any assets, books of account, registers or other documents in his possession, custody or control relating to the grant; or

(d) wrongfully obtains possession of, or retains any property forming part of the grant; or

(e) wrongfully removes or destroys any property forming part of the grant; or

(f) wrongfully uses any property forming part of the grant,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

Cognizance
of offences.

15. (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, no court shall take cognizance of any offence under this Act except on a complaint in writing made by the Government, or any officer authorised in that behalf by the Government.

2 of 1974

(2) Notwithstanding anything contained in section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973, it shall be lawful for any Magistrate of the First Class, specially empowered by the Government in this behalf, to impose a sentence of fine exceeding five thousand rupees when awarding punishment under section 14.

2 of 1974

Protection
of action
taken in
good faith.

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any employee of the Government, or the Special Officer appointed under section 6, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.

Power to
make rules.

17. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) The rules under this section shall be made subject to the condition of previous publication.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly for a period of fourteen days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Legislative Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

SCHEDULE

[See section 2(d)]

DESCRIPTION OF THE FORESTS INCLUDED IN THE KUTLEHAR FORESTS

Sl. No.	Name of Forests
1	2

DEMARCATED PROTECTED FORESTS :

District : HAMIRPUR

- (1) THETHU
- (2) CHATRAH
- (3) BAN MASLANA
- (4) CHELLI-SAT RUKHA
- (5) SASAL

District : UNA

- (6) PANIALA
- (7) THAPAL
- (8) BORU
- (9) RAMGARH-WARLA
- (10) RAMGARH-PARLA
- (11) TANDA
- (12) KANURA
- (13) SOLA SINGHI AND BHIAMBI
- (14) CHARARA
- (15) BAN DHANET
- (16) KARIARA
- (17) CHAROLI
- (18) SARKARU AND GHOR PLANI
- (19) OEL-DA-BAN
- (20) BEALA
- (21) DHIUNSAR
- (22) AKOI-DI-DHAR
- (23) CHANGRERI
- (24) THANA DULEHRI
- (25) TANDA BAGWAIN
- (26) TIRA AGHLAUR
- (27) BUSAL
- (28) GHUGAN KAKRANA
- (29) KAWARI
- (30) MAU
- (31) KATOH
- (32) AMROH
- (33) ATIA
- (34) CHAUKI MANIAR
- (35) JOL
- (36) KHARIAN
- (37) CHAOLI
- (38) CHAPLAH GARLAN

1

2

-
- (39) SOHARI BADUHA
 - (40) SARI
 - (41) CHAPLAH-KUTLEHRIAN
 - (42) BHARMAUT
 - (43) CHHATEHR
 - (44) BHIAMBI
 - (45) SUKRIAL
 - (46) MATOH
 - (47) KOT
 - (48) CHAMIARI
 - (49) BASATAR

UNDEMARCATED PROTECTED FORESTS :

District : UNA

- (1) MACHHAHLI
- (2) DHAR CHAMUKHA
- (3) KOTLA
- (4) ARLOO
- (5) SOLASINGI
- (6) MOMANIAR
- (7) CHAUKIMANIAR
- (8) BEH
- (9) KHARIALTA
- (10) DHANET
- (11) HEROO
- (12) DHIUNGLY
- (13) THARRA
- (14) TIRA

District : HAMIRPUR

- (15) GIARAN-GRAN
 - (16) PANJ-GRAN
-